एफ-11014/1/2015-जल ।।-भाग (5)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

****

चौथा तल,पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 01 अप्रैल, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
(ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी)
सभी राज्य सरकारें

विषय : ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में जीरो लीकेज।

महोदय,

इस मंत्रालय को कुछ मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिसमें यह बताया गया है कि 50 प्रतिशत पीने योग्य पेयजल उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले ही लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है और यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और भी खराब है।

यह स्पष्ट है कि जन जल वितरण प्रणाली में सस्ते और टूटने योग्य प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग ही इन भारी मात्रा में लीकेज के लिए जिम्मेदार है।

चूँकि, देश अस्थिर मानसून और कई क्षेत्रों में दूषित जल के कारण पहले ही पेयजल की कमी का सामना कर रहा है, अनुरोध है कि उपयुक्त गुणवत्ता वाली पाइपों का प्रयोग करके जल की लीकेज को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव (जल)

प्रति: श्री आयुष कुमार, संयोजक, सेव वाटर सोसाइटी, 58/5, बिरहाना रोड, कानपुर, पिन-208001

- 85820 -

प्रधान मंत्री कार्यालय

Prime Minister's Office

नई दिल्ली- 110011
New Delhi- 110011

Sub:Petition of SHRI AYUSH KUMAR
SAVE WATER SOCIETY
58/5 BIRHANA ROAD
KANPUR NAGAR
UTTAR PRADESH

A letter/gist of oral representation dated 14/02/2016 received in this office from SHRI AYUSH KUMAR is forwarded herewith for action as appropriate. Reply may be sent to the Petitioner and a copy of the same may be uploaded on the portal.

[V.B.Hariharan]
Section Officer

SECRETARY,MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

PMO ID No.:PMOPG/D/2016/0047170 Dated: 23/02/2016

Save Water Society

585, Birhana Road,Kanpur-208001 Ph: 0512-3012764 email : savewaters@gmail.com
Convenor : Ayush Kumar

14.2.16.

The Prime.Minister of India.
Govt. of India,
7, Race Course Road,
New-Delhi-110001.

Sub: Policy for Zero leakage in Rural and Urban Water Supply Schemes.

According to Research Reports from Singapore, in Indian cities about 50% potable water leaked before it reaches consumer (copy enclosed). In Rural areas conditions are much worse.

Bulk of the leakages is due to use of cheap and breakable plastic pipes (PVC/HDPE) in potable water distribution system. If we use metallic pipe in water distribution, we may reduce this leakage to bare minimum. These metallic pipes are available in India easily.

We request you to announce a policy for zero leakage in rural/urban potable water supply schemes.

The Central Govt. and State Govts together invest about 20000 Crores every year for providing safe drinking water to its people. If we achieve zero leakage we may increase the availability of potable water by 100% without any further investment through this Policy.

With kind regards.

Yours truly,
For Save Water Society,

(Ayush Kumar)

Dainik Jagran Kanpur Edition 14.2.2016

नीतियों और तरीकों में हो सुधार

-अरित के बिस्वास
(विजिटिंग प्रोफेसर, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर)

विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2016 तैयार करने के लिए दुनिया भर के 750 विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों की अवधि में उत्पन्न होने वाले सबसे बड़े वैश्विक खतरों की संभावना और प्रभावों के संबंध में विचार मांगे। विशेषज्ञों ने 29 पृथक खतरों का उनके महत्व के आधार पर आकलन किया। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के असर को रोकने के लिए कम किए जा रहे प्रयास को मौजूदा सबसे बड़े वैश्विक संकट के रूप में पहचान की गई और जल संकट को तीसरी सबसे बड़ी समस्या बताया गया। यदि अगले 10 वर्षों में संभावित प्रभावों के आधार पर विचार किया जाए तो 40 प्रतिशत विशेषज्ञों ने जल संकट और 37 प्रतिशत ने जलवायु परिवर्तन को चयनित किया।

भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। देश में उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर जलीय दबाव के चिन्ह दिखते हैं। दशकों से इस्तेमाल की जा रही कमजोर नीतियों और तौर-तरीकों के कारण बाकी देशों की तुलना में भारत की जलीय स्थिति बदतर है। वरिष्ठ नीति निर्धारकों में इस मसले पर सतत रुचि सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखती। गंभीर बाढ़ और सूखे के दौरान ही राजनेताओं की इस ओर रुचि दिखती है। इन आपदाओं के समाप्त होते ही वह रुचि भी समाप्त हो जाती है। तमाम कारकों के चलते देश में जल की मांग आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने के संकेत हैं। इन परिस्थितियों में यदि देश पहले से चले आ रहे असंतोषजनक और गैर टिकाऊ जल प्रबंधन नीतियों को बरकरार रखता है तो अगले 10-20 वर्षों में इसे गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि देश की जलीय दशाओं के इतना भयावह होने की आशंका नहीं दिखती। तेल, गैस और सभी खनिजों की तुलना में जल नवीकरणीय संसाधन है। सही प्रबंधन के साथ पानी का एक बार उपयोग होने के बाद शोधित कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा ज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन के तौर-तरीकों और समस्त क्षेत्रों में सक्षम उपयोग के साथ अगले कई दशकों तक सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के पास भरपूर जल है। कमजोर प्रबंधन की खामी के रूप में देश के शहरी जल प्रबंधन का हाल देखा जा सकता है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां सातों दिन, 24 घंटे पानी की सप्लाई होती हो और बिना स्वास्थ्य चिंता के सीधे नल की टोंटी से पानी पिया जा सके। इस कारण हर शहरी घर एक लघु-जल संयंत्र बन गया है। एक दिन में कुछ घंटे ही पानी मिलने के कारण वे घर में लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टैंकों में पानी एकत्र करते हैं। 10 साल पहले घरों में साधारण फिल्टर से पानी का शोधन किया जाता था। अब जल की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि बड़ी संख्या में परिवार रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) का इस्तेमाल करते हैं।

भारत को अपनी मौजूदा लचर जल प्रबंधन नीतियों और तौर-तरीकों को सुधारना ही होगा। यह संभव है और इसके अलावा देश के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

घरेलू जलापूर्ति मुफ्त है या इस पर अत्यधिक सब्सिडी है। ऐसे में एक ऐसा उपयुक्त वित्तीय मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जहां केवल गरीब को लक्षित सब्सिडी सुविधा मिले बाकी सबसे उपयोग किए जल और इसके खराब जल के शोधन की पूरी कीमत ली जाए।

-सेसीलिया टोरटाजादा
(सीनियर रिसर्च फेलो, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर)

भारतीय शहरों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले समस्त जल का 40-50 प्रतिशत हिस्सा लीकेज और खराब प्रबंधन के कारण बेकार चला जाता है। नोम पेन्ह में यह नुकसान महज 6-7 प्रतिशत है। इस लिहाज से भारत भले ही उभरती हुई आर्थिक शक्ति हो लेकिन इसके शहरी जल प्रबंधन तौर-तरीके नोम पेन्ह जैसे कम विकसित शहरों से पीछे हैं।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या देश के समक्ष यह है कि शहरी केंद्रों के भीतर या निकट लगभग सभी जल निकाय अत्यधिक प्रदूषित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 445 नदियों में से तकरीबन आधी जैविक वर्ज्य पदार्थों और कोलीफार्म बैक्टीरिया की वजह से अत्यधिक प्रदूषित हैं। यदि अन्य प्रदूषकों मसलन नाइट्रेट, फ्लोराइड, खतरनाक रसायन और भारी धातुओं की दृष्टि से देखा जाए तो देश की किसी भी नदी का पानी बिना सघन शोधन के पीने योग्य नहीं है। गंगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं।

भारत की जलीय समस्याओं का समाधान संभव है। इसके लिए सतत राजनीतिक इच्छा, मजबूत जल संस्थानों के निर्माण और सरकारी धन का सक्षम तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। जनता को भी स्वीकार करना होगा कि उन्हें तभी बेहतर जल सुविधाएं मिलेंगी जब उपयुक्त शुल्क और टैक्सों के माध्यम से वे लागत का भुगतान देंगे। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के यदि कारगर उपाय नहीं किए गए तो निश्चित रूप से अगले दो दशकों के भीतर अविश्वसनीय जल संकट से जूझना होगा।